

cf
S174

'Collaborative action key to fighting human trafficking'

STAFF REPORTER

GUWAHATI, July 31: The Assam State Commission for Protection of Child Rights, in collaboration with the British Deputy High Commission, Kolkata, organised a daylong interactive group discussion among stakeholders on World Day against Trafficking in Per-

sons, with special focus on children, here yesterday.

Speaking on the occasion, ASCPCR Chairperson Dr Sunita Changkakati welcomed all the stakeholders and laid stress on understanding the growing evil of human trafficking and the emerging waves of this dark trade, which threatens the lives of innocent

women and children.

Addressing the house, IGP of CID Surendra Kumar presented an analysis of the trafficking scenario in Assam.

The discussion proceeded with screening of a film titled Taken on trafficking survivors of Assam, directed by Angshu Kotoky. Taken, as the title suggests, explores remote villages of lower Assam where almost each household has lost one family member to this vicious trade of human trafficking. One brave woman, who is a survivor of trafficking and shares her experiences in the film, was also present amongst the stakeholders during the discussion.

Special DG (Railways) R Chandranathan spoke about his experiences as a police officer in various parts of the country. He elaborated on the desire of individuals to seek a good life and the paradoxes of a good

life, which often involves a heavy price to be paid.

The programme concluded with a vote of thanks from Shaida Khan, Deputy Mission Head, British Deputy High Commission, Kolkata, who appreciated the interactive discussion among stakeholders and the efforts of the Assam State Commission for Protection of Child Rights for providing an open platform to everyone present to share their views.

The dialogue for stronger implementation of policies and a need for inter-agency collaboration emerged as the way forward from the discussion. The programme was attended by stakeholders from police, legal services authority, social welfare, child line, UNICEF civil society organisations, professors and students.

दिल्ली महिला आयोग ने ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को भेजा समन

नई दिल्ली। पहाड़गंज से 39 नेपाली युवतियों को छुड़ाने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को समन जारी


**पहाड़गंज से 39
नेपाली युवतियों को
छुड़ाने का मामला**

किया है। आयोग ने पूछा है कि पुलिस को इतनी बड़ी संख्या में नेपाली मूल की युवतियों के ठहरने की जानकारी थी या नहीं। आयोग ने पूछा है कि अब तक इस मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। युवतियों की शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक रिपोर्ट दर्ज क्यों

नहीं की। साथ ही उन्हें पूरे दिन थाने में रखने की जानकारी भी मांगी है। आयोग ने 164 सीआरपीसी के अंतर्गत युवतियों के बयान नहीं कराने की वजह, होटल और उसके आसपास के क्षेत्रों की सीसीटीवी फुटेज, बरामद दस्तावेजों की जानकारी भी मांगी है। आयोग ने इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर को 6 अगस्त को आयोग के समक्ष पेश होकर जवाब देने को कहा है। ब्यूरो

मुनिरका से मुक्त कराई 16 युवतियां नेपाल भेजीं



नई दिल्ली | वरिष्ठ संवाददाता 

राजधानी में हाल ही में अलग-अलग जगहों से मुक्त कराई गई नेपाली मूल की युवतियों को उनके घर पहुंचाया जाएगा। नेपाल दूतावास के साथ मिलकर युवतियों को उनके परिजनों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले चरण में 16 युवतियों को उनके परिजनों के पास पहुंचाया गया है।

दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने गुरुवार को कहा कि नेपाल में हुई भूकंप त्रासदी के बाद से वहां मानव तस्करी के मामले बढ़े हैं। ये

युवतियां दोबारा इसकी शिकार न हों इसके प्रयास किए जा रहे हैं। 24 जुलाई को मुनिरका इलाके से 16 नेपाली लड़कियों को मुक्त कराया था। एक दिन पहले फिर से 39 नेपाली लड़कियां छुड़ाई गईं। बनारस से आई पुलिस ने भी 18 लड़कियों को मुक्त कराया था।

मुनिरका से मुक्त कराई गई नेपाली मूल की लड़कियों ने बातचीत के दौरान बताया था कि वे भूकंप प्रभावित इलाके से हैं और वापस अपने घर जाना चाहती हैं। युवतियों की मांग पर नेपाली दूतावास की मदद से इन लड़कियों को उनके घर पहुंचाया गया।

नेपाल सरकार को पत्र लिखा: मुक्त कराई गई युवतियां दोबारा तस्करों की शिकार न हों इसलिए जरूरी है कि नेपाल सरकार उन्हें वहीं रोजगार उपलब्ध कराए। इस सिलसिले में नेपाल सरकार को पत्र लिखा गया है।

स्वाति पर बिफरीं छुड़ाई गई नेपाली लड़कियां

4/ef

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: पहाड़गंज के होटल से मुक्त कराई गई 39 नेपाली लड़कियों को नारी निकेतन में रखा गया है। बृहस्पतिवार सुबह दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद जब उनसे दोबारा पूछताछ करने पहुंचीं तो कई लड़कियां उनपर बिफर गईं। उन्होंने कहा कि रोजगार की तलाश में वे खुद दिल्ली आई थीं, लेकिन उनपर वेश्यावृत्ति का घंघा करने का आरोप लगा बदनाम कर दिया गया।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आठ लड़कियों ने स्वाति जयहिंद से कहा कि वे अब किसी सूत में वापस नेपाल नहीं जाएंगी, क्योंकि उनकी बदनामी हो गई है। इन लड़कियों ने दिल्ली महिला आयोग के रवैये पर जमकर हंगामा किया। हालांकि, बाद में पुलिस ने इन्हें शांत कराया। पुलिस का कहना है कि नारी निकेतन से इन आठों लड़कियों को



पहाड़गंज के एक होटल से नेपाली मूल की युवतियों को मुक्त कराकर ले जाती दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जयहिंद • फाइल फोटो

शुक्रवार को छोड़ दिया जाएगा। शेष 31 लड़कियों के मामले में नेपाल दूतावास ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। सूत्रों के

मुताबिक, नेपाल दूतावास ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष के बयान पर घोर आपत्ति

जताई है। दूतावास के अधिकारी ने पूछा है कि किस आधार पर इन लड़कियों पर वेश्यावृत्ति में संलिप्त होने का आरोप लगाया जा रहा है।

ज्ञात हो कि मंगलवार देर रात 1.30 बजे महिला आयोग की सूचना पर दिल्ली पुलिस ने नेपाल मूल की 39 लड़कियों को पहाड़गंज मेन बाजार स्थित होटल हृदय से मुक्त कराया था। ये लड़कियां अलग-अलग तिथियों में अपने रिश्तेदारों व खास परिचितों के साथ नेपाल से रोजगार की तलाश में दिल्ली आई थीं और अलग-अलग कमरे में ठहरी हुई थीं। सभी ने होटल में ठहरने के लिए जरूरी दस्तावेज मुहैया कराए थे। पुलिस का कहना है कि लड़कियों को कमरे से बाहर निकालकर दूसरे कमरे में ले जाया गया, जहां स्वाति जयहिंद ने उनसे अकेले में घंटों बात की। उस दौरान महिला पुलिस को भी बाहर निकाल दिया गया।

Women's rescue from Paharganj: DCW summons police officer

Information sought regarding arrests made in the case

STAFF REPORTER

NEW DELHI

The Delhi Commission for Women (DCW) on Thursday summoned the Joint Commissioner of Police (Central) over the action taken in connection with the rescue of 39 women allegedly trafficked from Nepal.

The DCW has asked the senior police officer to appear before it on August 6 to provide information regarding the arrests made till date.

Notice

"With reference to the rescue of 39 women from a hotel in Paharganj, [provide] action taken report and reasons for non-registration of FIR on the complaints received from them and reasons for not producing them before the Magistrate concerned for recording the



Thirty-nine women from Nepal were rescued from a hotel in Paharganj on July 25. ■ FILE PHOTO

statements," read the notice.

The women's commission has also asked the police for CCTV camera footage of the hotel and adjoining areas.

"The manner in which such large number of women have been found in discrete locations prima facie indicates operations of a

huge and strong nexus of human traffickers. Moreover, the fact that such large number of Nepalese women are being brought to Delhi and sent abroad raises concerns regarding the role of various agencies especially of the police," read the letter to the police.

अब तक न तो FIR हुई और न गिरफ्तारी

पहाड़गंज मामले : स्वाति ने जॉइंट कमिश्नर को किया समन

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

पहाड़गंज के होटल से छुड़ाई गई 39 लड़कियों के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस देकर पूछा है कि क्यों अब तक इस मामले में एफआईआर नहीं की गई और न ही गिरफ्तारी हुई। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति जय हिंद ने दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर, सेंट्रल रेंज को समन भेजकर 6 अगस्त को 2:30 बजे आयोग के सामने पेश होने को कहा है। आयोग ने पुलिस से पहाड़गंज होटल और उसके आसपास के इलाके के पिछले 15 दिनों की फुटेज भी मांगी है। छापे वाले दिन के भी फुटेज पेश करने को कहा गया है।

आयोग ने दिल्ली पुलिस के डीले रवैये की ओर इशारा करते हुए जॉइंट कमिश्नर, सेंट्रल रेंज को समन किया है। 31 जुलाई की रात और 1 अगस्त की सुबह पहाड़गंज होटल में रेड डालकर छुड़ाई गई 39 नेपाली लड़कियों को लेकर आयोग की चेयरपर्सन स्वाति जय हिंद ने पूछा है कि क्यों बुधवार सुबह लड़कियों को लिखित शिकायतों के मिलने के बावजूद पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर नहीं की। आयोग ने ये शिकायतें भी जॉइंट कमिश्नर को भेजी हैं। आयोग ने पूछा कि 39 लड़कियों को बुधवार दिन से देर शाम तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में क्यों रखा गया? क्यों उन्हें शेल्टर होम नहीं भेजा गया, जबकि सुबह 11 बजे ही सबका मेडिकल हो चुका था। स्वाति का कहना है कि लड़कियों को सूरज डूबने के बाद ही शेल्टर होम भेजा गया, जबकि वो सुबह से शाम तक कई बार एसएचओ को फोन करती रहीं।

आयोग ने सवाल किया है कि लड़कियों का बयान रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया, जो कि सेक्शन 164 सीआरपीसी का उल्लंघन है।



स्वाति ने पूछा

- 39 लड़कियों को बुधवार दिन से देर शाम तक पुलिस स्टेशन में हिरासत में क्यों रखा गया?
- लड़कियों का बयान रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया गया
- क्या विदेशी नागरिकों के होटल में रहने को लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए थे?

पहाड़गंज से छुड़ाई गई लड़कियों से मिली स्वाति

पहाड़गंज से छुड़ाई गई 39 लड़कियां शेल्टर होम में हैं और गुरुवार को उनसे मिलने दिल्ली महिला अयोग की चेयरपर्सन स्वाति जयहिंद पहुंचीं। उनके साथ नेपाल एंबेसी के अधिकारी भी शेल्टर होम गए और लड़कियों की बात सुनीं। स्वाति ने बताया कि लड़कियों ने नेपाल के अधिकारियों से भी यही कहा है कि उन्हें नौकरी देने के नाम पर दूसरे देशों में ले जाया जा

रहा था। हालांकि, कई लड़कियां कई दिनों से पहाड़गंज के होटल में ही थीं। उन्हें बाहर निकालने की इजाजत भी नहीं थी। लड़कियों ने गुजारिश की कि उन्हें वापस उनके घर नेपाल भेजा जाए और वहीं नौकरी दिलाई जाए। नेपाल के अधिकारियों ने बताया कि वे इन लड़कियों को वापस भेजने और वहां नौकरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसके अलावा आयोग ने पुलिस से लड़कियों के बयानों की कॉपी मांगी है और पूछा है कि क्या होटल 'हृदय इन' से कोई डॉक्यूमेंट जवाब किया गया? अगर हां, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, वहां से मिले रजिस्टर, सोज्योर मेमो, रोजनामचा रजिस्टर (डीडी एंटी के साथ) की कॉपी

भी दी जाए।

आयोग ने पूछा है कि क्या लोकल पुलिस को जानकारी थी कि होटल में इतनी बड़ी तादाद में नेपाली लड़कियां रह रही हैं। क्या विदेशी नागरिकों के होटल में रहने को लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करवाए गए थे?

Will new anti-trafficking Bill help?

The focus is more on the victims rather than the perpetrators of the crime

FLAVIA AGNES

IN a recent newspaper article titled, 'Why I pushed for passage of the anti-trafficking Bill', Union Minister for Women and Child Development Maneka Gandhi offered a justification for the haste with which the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018, was pushed through in the Lok Sabha on July 26, 2018: 'Because our children and women cannot wait any longer. A child in sexual exploitation and a woman in sexual slavery are looking up to us and questioning us on what we are doing as a civilised society and a welfare State'. She added, 'It was a matter of great urgency since every day thousands of children and women are trafficked and the society had a collective responsibility to respond to their desperate plea'.

The Bill is meant to go much further in its scope and reach than the prevailing Immoral Traffic Prevention Act (ITPA) and will address the issue of trafficking from the point of view of prevention, rescue and rehabilitation. It has defined 'aggravated' forms of trafficking, which includes trafficking for the purpose of forced labour, begging, trafficking by administering chemical substance or hormones on a person for the purpose of early sexual maturity, trafficking of a woman or child for the purpose of marriage or under the pretext of marriage, etc.

She offered an olive branch to all groups working with sex workers collectives who had expressed serious concerns that the Bill, if enacted, would violate the basic rights of women who are in the sex work industry of their own volition, and invited them to work together with the government 'so that differences could be ironed out and together we can learn and work in collaboration to push the boundaries of justice and empower the most vulnerable persons in our society'.

The minister assured that the provisions of the Bill had been carefully synchronised with all existing and linked provisions of law and structures created thereunder. It aims to supplement existing criminal law provisions on trafficking under Section 370 of the IPC and the Immoral Traf-



TO WHAT END? It's a fact: many who are 'rescued and rehabilitated' return to sex work.

fic (Prevention) Act 1956. The definition of trafficking is drawn primarily from Section 370, IPC, which includes 'any act of physical exploitation, sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery and servitude'. Trafficking under this Bill also includes begging, domestic work, farm or factory work.

But activists have pointed various gaps which fail to address the core concerns of trafficking and the lapses which threaten free speech and the right to work under Article 19 and the basic human dignity guaranteed under Arti-

The experiences of sex workers picked up during operations have brought out that this raid and rescue approach rarely addresses the issue of trafficking and, instead, results in debt bondage and large-scale rights violations of sex workers.

cle 21 of the Constitution. Meena Seshu of the National Network of Sex Workers, a strong and articulate voice in the movement to protect the dignity of sex workers and their right not just to work, but to survive, has been opposing this enactment in its current form for the past few years. According to her, the state administration has turned a deaf ear to their anguished pleas.

She explains that framing trafficking as an issue of morality wrongly assumes that no woman would enter sex work of her own volition. The experiences of sex workers picked up during raid and rescue operations have brought out the stark reality that the approach of 'raid, rescue and rehabilitation' rarely addresses

the issue of trafficking, and instead results in large-scale rights violations of sex workers with the underlying presumption that only trafficked women need to be rescued and rehabilitated.

The world over, anti-trafficking laws and policies have placed sex workers on the cusp of violence inflicted by law enforcers and anti-trafficking groups. The experiences of sex workers picked up during these operations reveal that this strategy rarely addresses the issue of trafficking. Anecdotal information gathered by sex worker rights activists

in India as well as studies conducted have brought out the harsh reality that many women who are 'rescued and rehabilitated' return to sex work. The ITPA, with 'immoral' and 'traffic' in its very title, suggests that trafficking is an issue of morality rather than a criminal offence. Its interpretation on the ground, therefore, adopts an anti-sex worker approach.

On the presumption of lack of consent, Section 17(2) of the ITPA states that a woman who is rescued as a consequence of raid and rescue operations can be handed over into the 'safe' custody of her husband or parents or guardian and this includes adult women who have consented to sex work. A magistrate satisfied about the

antecedents and suitability of the husband, parents or guardians, may issue an order granting custody to them.

This section, which infantilises adult women, is debilitating for women who are in sex work as adults living independent of parents or family. Many are heads of their households and primary providers for their families. In many cases, adult women do not inform their families that they are in sex work. When directed by the magistrate to produce a husband, parents and guardians in court, they are forced to contact family members in humiliating circumstances.

Instead of addressing the core issue of prevention of trafficking, the approach of raid, rescue and rehabilitate increases vulnerabilities of sex workers as they get further trapped into debt bondage and other exploitative practices. Fees to lawyers, surety for bail, bribes to officials and mounting daily expenses in the absence of income due to incarceration, force women released from correction homes to incur huge debts. Ironically, getting trapped in a cycle of debt bondage is a consequence of a raid and rescue strategy which is purportedly designed to help these women.

While this is the current situation, the Bill, when enacted, will make the situation far worse in the name of protection and prevention. It will lead to greater surveillance and adult victims will be sent to rehabilitation homes or repatriated to their places of origin. Aarthi Pai, another activist involved with Sangram, a sex worker collective, points out: 'There is no provision provided if 'victims' do not want to go to rehabilitation or accept repatriation which is against Article 19(1)(g) of the Constitution which guarantees the fundamental right to work.'

The key notions underlying Article 21 are dignity and autonomy. While admitting that trafficking is clearly a criminal offence that requires strict measures to combat unscrupulous persons and criminal networks, activists point out how all measures to deal with trafficking in the Bill focus on the victims rather than the perpetrators of the crime.

Mumbai-based women's rights lawyer